

Project Sustainability & Exit Policy

03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तराखण्ड राज्य की पर्वतीय महिलाओं के कार्यबोझ में स्थायी रूप से कमी एवं उनके आजीविका स्तर में सुधार लाते हुए उनका सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण करना है, के तहत दिनांक 25 नवम्बर 2013 से 27 नवम्बर 2013 तक तीन दिवसीय “**Project Sustainability & Exit Policy**” (परियोजना सतता एवं निर्गम नीति) प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हिमालयन टार्च बियरर, कुठाल गेट, देहरादून में किया गया है। श्रीमति निधि मणि त्रिपाठी जी, निदेशक/अपर सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा सत्र का शुभारम्भ दीप प्रज्वलित कर किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए श्रीमति निधि मणि त्रिपाठी, निदेशक/अपर सचिव महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा अपने सम्बोधन में सर्वप्रथम उत्तराखण्ड महिला एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना के निर्माण एवं सोच पर प्रकाश डालते हुए अवगत कराया कि सहयोगी संस्थाएँ जमीनी स्तर पर कार्य कर समाज में बदलाव लाने का कार्य करती हैं। उत्तराखण्ड महिला समेकित विकास योजना के द्वारा उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सभी सहयोगी संस्थाओं को उचित मार्गदर्शन एवं सहयोग इस प्रशिक्षण के दौरान दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण परियोजना के महिला लाभार्थियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में अतिमहत्वपूर्ण सिद्ध होगा।

उनके द्वारा संस्था प्रतिभागियों से यह अपेक्षा की गयी कि सम्बन्धित प्रशिक्षण उपयोग संस्थाओं द्वारा अपनी कार्यप्रणाली में अपनाते हुए परियोजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये गये प्रशिक्षण का समुचित उपयोग करते हुए महिला रोजगार एवं उद्यमों के अवसरों का सृजन करेंगी, जिससे महिलाएँ स्वावलम्बन की ओर अग्रसर होंगी।

इस अवसर पर सुश्री आरती बलोदी, राज्य परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इस कार्यक्रम में राज्य के 12 जनपदों के 68 विकासखण्डों की 33 संस्थाओं के लगभग 50 प्रतिभागियों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य परियोजना के तहत चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को उनके लाभार्थियों, स्वयं सहायता समूहों को अधिकतम लाभ देते हुए परियोजना के अन्तिम चरण में परियोजना सतता का निर्माण कर निर्गम नीति का स्वरूप तैयार कर ग्रामीण स्तर पर अपनायी जा सके। साथ ही विशिष्ट अतिथि श्रीमति कविता नबियाल, वित्त नियंत्रक, द्वारा योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य द्वारा पारित उत्तराखण्ड क्रय प्रणाली 2008 के प्रमुख बिन्दुओं पर प्रकाश डालते लेखा सम्बन्धी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर जानकारी प्रदान की गयी। ताकि वित्त सम्बन्धी अनिमितताएँ ना हो सकें। उक्त अवसर पर विभाग के कार्यक्रम प्रबन्धक श्री अखिलेश मिश्र, सन्दर्भ व्यक्ति श्री विनोद मिश्रा, राष्ट्रीय सलाहकार, श्री अजित तोमर, एवं योजना से रवि मेलवान, प्रदीप तिवारी आदि उपस्थित रहे।